Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

Original Article

भागलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना का प्रभावः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ.रीता कुमारी
पी-एच. डी. पंजीयन स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, ति. माँ. भा.वि. वि., भागलपुर
Email: kumarireeta792@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2025-171109
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 11(A)
Pp. 56-64
November. 2025
Submitted: 16 oct. 2025
Revised: 26 oct. 2025
Accepted: 10 Nov. 2025
Published: 30 Nov. 2025

सारांश

'भागलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना का प्रभावः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण' के अंतर्गत ICDS योजना भागलपुर के सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बाल पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में उभरकर सामने आया है। यह केवल एक कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ग्रामीण सामाजिक संरचना, लैंगिक संबंध और सामुदायिक सहभागिता को प्रभावित करने वाला एक संस्थागत ढाँचा है।

ICDS योजना का मुख्य प्रभाव बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। आँकड़ों (NFHS–5) के अनुसार, बच्चों में अनन्य स्तनपान (Exclusive Breastfeeding) की दर राज्य के औसत से बेहतर है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से लाए गए सफल व्यवहार परिवर्तन का संकेत है। जिले में नाटापन (Stunting) और एनीमिया का उच्च स्तर राज्य के औसत से काफी खराब है। दीर्घकालिक पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में असमानता और गुणवत्ता की चुनौती अभी भी बनी हुई है।

योजना का गहरा समाजशास्त्रीय प्रभाव महिलाओं देखने को मिलता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रूप में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, सामाजिक पहचान और सामुदायिक नेतृत्व का अवसर मिला है। केंद्रीय सामुदायिक नेटवर्क और सामाजिक पूंजी के निर्माण का माध्यम बन रहा है, जो पितृसत्तात्मक संरचना के अंतर्गत महिलाओं के निर्णय–प्रक्रिया में भागीदारी और आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। कार्यान्वयन संसाधनों की अपर्याप्तता, बुनियादी ढांचे की कमी, खाद्यान्न आपूर्ति में अनियमितता, कार्यकर्ताओं के अपर्याप्त वेतन और प्रशिक्षण की कमी जैसी चुनौतियों से घिरा हुआ है। सामाजिक असमानताएँ (जातिगत भेदभाव) और प्रशासनिक लापरवाही भी योजना के पूर्ण लाभ को कमजोर वर्गों तक पहुँचने से रोकती है। योजना ग्रामीण भागलपुर में सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त उपकरण बनकर उभरा है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता को और स्थायी बनाने के लिए नीतिगत सुधार आवश्यक है। इसके लिए संसाधनों को बढ़ाना, मानव संसाधन को सुदृढ़ करना, डिजिटल निगरानी और स्थानीय सामाजिक–सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना प्रमुख नीतिगत सुझाव है।

शब्द कुंजी– *अनन्य स्तनपान, नाटापन, एनीमिया, सामुदायिक नेतृत्व, केंद्रीय सामुदायिक नेटवर्क, सामाजिक पूंजी, पितृसत्तात्मक संरचना, खाद्यान्न आपूर्ति, अनियमितता, प्रशासनिक लापरवाही, प्रभावशीलता, सामाजिक–सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सामुदायिक सहभागिता।*

परिचय

एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना, भारत सरकार की सबसे व्यापक और प्रभावशाली सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिशुओं, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा छह वर्ष तक के बच्चों के समग्र पोषण एवं विकास को सुनिश्चित करना है। योजना केवल स्वास्थ्य एवं पोषण पर ही केंद्रित नहीं है, इसका व्यापक उद्देश्य ग्रामीण समाज में बाल कल्याण और महिला सशक्तिकरण की सामाजिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है। भागलपुर ज़िला बिहार राज्य का सामाजिक रूप से विविध और आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण जैसी समस्याओं का सामना करते हैं।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ.रीता कुमारी, पी-एच. डी. पंजीयन स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, ति. माँ. भा.वि. वि., भागलपुर

How to cite this article:
कुमारी, . रीता . (2025). भागलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना का प्रभावः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण. Journal of Research and Development, 17(11(A)), 56–64.
https://doi.org/10.5281/zenodo.17959897

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.17959897
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

"क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक–आर्थिक विषमताओं के मध्य गहरी खाई है, विशेष रूप से महिलाएँ व बच्चे इन असमानताओं से बड़े पैमाने पर प्रभावित है।"[1]

इस प्रकार की पृष्ठभूमि में ICDS जैसी योजना ग्रामीण जीवन के सामाजिक ढांचे को समझने और इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से योजना को केवल एक कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता है, यह ग्रामीण संरचना, लैंगिक संबंध, परिवार और समुदाय की सहभागिता तथा राज्य और समाज के बीच संबंध को भी परिभाषित करता है। "आंगनवाड़ी केंद्र केवल बच्चों के पोषण और शिक्षा का स्थल नहीं है, यह ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार, सामुदायिक नेटवर्किंग और सामाजिक मान्यता का भी माध्यम है।"[2] इस प्रकार, योजना ग्रामीण समाज में सामाजिक पूंजी और सामूहिकता के निर्माण का आधार बनाता है।

भागलपुर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का कार्यान्वयन कई स्तरों पर सामाजिक परिवर्तन का संकेत देता है। एक ओर यह योजना कुपोषण, बाल मृत्यु दर और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं से लड़ने का प्रयास करता है, तो दूसरी ओर महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, आत्मनिर्भरता और जागरूकता में भी योगदान देता है। "इसके साथ–साथ कई चुनौतियाँ भी मौजूद है, जैसे–अपर्याप्त संसाधन, संरचनात्मक कमी और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही।"[3]

अध्ययन का उद्देश्य भागलपुर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में ICDS योजना के प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इसके साथ ही यह भी अध्ययन किया जाएगा, किस प्रकार यह योजना केवल बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुधार तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक संरचना, लैंगिक भूमिकाओं और समुदाय की सहभागिता को भी प्रभावित करता है। विश्लेषण के द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि ICDS ग्रामीण विकास के व्यापक विमर्श में किस हद तक एक सशक्त हस्तक्षेप है और इसके सामाजिक प्रभाव कितने स्थायी और गहरे हैं।

ICDS योजना – एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

योजना का उद्भव केवल स्वास्थ्य और पोषण सुधार की सरकारी रणनीति के रूप में नहीं हुआ है, यह एक व्यापक सामाजिक हस्तक्षेप है, जिसने ग्रामीण समाज की संरचना, लैंगिक संबंध और समुदाय की सहभागिता पर गहरा प्रभाव डाला है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, "योजना को केवल 'पोषण कार्यक्रम' के रूप में नहीं देखा जाता है, इसे एक ऐसा संस्थागत ढाँचा माना जाना जाता है, जो ग्रामीण सामाजिक जीवन को पुनर्गठित करता है।"[4]

योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, यह ग्रामीण समाज में बच्चों और महिलाओं की स्थिति को प्रकाश में लाता है। भारत जैसे देश में, जहाँ लंबे समय तक बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को उपेक्षा का सामना करना पड़ा, वहीं यह योजना ग्रामीण सामुदायिक समूह को विकास प्रक्रिया का केंद्र बनाया है। "आंगनवाड़ी केंद्र न केवल पोषण वितरण और स्वास्थ्य परामर्श का स्थल है, बल्कि यह ग्रामीण समाज में राज्य और नागरिकों के बीच संवाद का एक माध्यम भी है।"[5]

समाजशास्त्रीय दृष्टि से ICDS योजना को प्रकार्यवादी (Functionalist) और संघर्षवादी (Conflict) दोनों परिप्रेक्ष्यों से समझा जा सकता है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार, योजना ग्रामीण समाज की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करती है। "बच्चों और माताओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करके यह समाज के दीर्घकालिक पुनरुत्पादन (Social Reproduction) को सुनिश्चित करता है।"[6] दूसरी ओर, संघर्षवादी दृष्टिकोण के अनुसार, योजना राज्य द्वारा ग्रामीण असमानताओं को प्रबंधित करने और वर्ग–आधारित विषमताओं को नियंत्रित करने का उपकरण है। "योजना की सीमा संसाधनों की कमी और भ्रष्टाचार की समस्याएँ इस बात की और संकेत करता है, हाशिए पर मौजूद समूहों को अब भी योजनागत लाभ से पूर्ण रूप से वंचित रखा जा रहा है।"[7]

इसके अतिरिक्त, लैंगिक दृष्टिकोण से योजना का विशेष महत्व है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक श्रम क्षेत्र से जोड़ता है। यह न केवल रोजगार प्रदान करता है, सामुदायिक स्तर पर उनकी पहचान और प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। इस प्रकार, "ICDS ग्रामीण समाज में लैंगिक भूमिका के पुनर्गठन के रूप में कार्य करता है।"[8]

योजना को ग्रामीण सामाजिक पूंजी (Social Capital) के निर्माण की प्रक्रिया से भी जोड़ा जा सकता है। आंगनवाड़ी केंद्र एक सामुदायिक स्थल के रूप में काम करता है, जहाँ महिलाएँ, बच्चे और परिवार एक साथ आते हैं। यह आपसी विश्वास, सहयोग और सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार योजना "ग्रामीण समाज में सहभागितामूलक लोकतंत्र और सामूहिकता की भावना को भी विकसित करता है।"[9] अतः समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से योजना केवल सेवा वितरण का सरकारी योजना नहीं है, यह ग्रामीण समाज की गतिशीलता, शक्ति संरचना और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

---

1 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO). (2020). *बिहार में घरेलू उपभोग और सामाजिक संकेतक: NSS 76वां चक्र (2018–19)*. नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

2 बसु, एम., एवं दास, एस. (2018). *ICDS के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी और महिला सशक्तिकरण: ग्रामीण भारत का अध्ययन*. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।

3 पटेल, डी. (2019). *भारत के पिछड़े जिलों में ICDS के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: क्षेत्राधारित अध्ययन. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़*, 35(3), 133–150।

4 सेन, ए., एवं द्रेज़, जे. (2013). *अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स*. प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

5 बसु, एम., एवं दास, एस. (2018). *ICDS के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी और महिला सशक्तिकरण: ग्रामीण भारत का अध्ययन*. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।

6 पार्सन्स, टी. (1951). *द सोशल सिस्टम*. ग्लेंको, इलिनॉय: फ्री प्रेस।

7 पटेल, डी. (2019). *भारत के पिछड़े जिलों में ICDS के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: क्षेत्राधारित अध्ययन. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़*, 35(3), 133–150।

8 कबीर, एन. (2001). *महिला सशक्तिकरण के मापन पर चिंतन. डिस्कसिंग विमेन्स एम्पावरमेंट: थ्योरी एंड प्रैक्टिस* (पृ. 69–88). स्टॉकहोम: सिडा स्टडीज़।

9 पटनम, आर. (2000). *बोलिंग अलोन: अमेरिकन समुदाय का पतन और पुनरुत्थान*. न्यूयॉर्क: साइमन एंड शुस्टर।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

सामाजिक–आर्थिक परिदृश्यः ग्रामीण भागलपुर

भागलपुर ज़िला बिहार के दक्षिण–पूर्वी हिस्से में स्थित है और यह गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक व सामाजिक रूप से विविध क्षेत्र है। ज़िला अपनी सांस्कृतिक विरासत और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से यह अभी भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार, "ज़िले की लगभग 75 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि यहाँ का प्रमुख आजीविका स्रोत है।"[10]ग्रामीण भागलपुर की सामाजिक संरचना जाति–आधारित पदानुक्रम और वर्गीय विभाजन से गहराई से प्रभावित है। उच्च जाति के पास भूमि और आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण है, जबकि दलितों और पिछड़ी जातियों की बड़ी आबादी भूमिहीन श्रमिकों और छोटे किसानों के रूप में जीवन–यापन करती है। "यह सामाजिक असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक पहुँच में भी दृष्टिगोचर होता है।"[11] महिलाओं और बच्चों की स्थिति विशेष रूप से कमजोर है। कुपोषण, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक पाई जाती है।

आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार, ग्रामीण भागलपुर में रोजगार का स्वरूप मुख्यतः असंगठित और मौसमी है। बड़ी संख्या में लोग प्रवासी मज़दूरी विशेषकर दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर निर्भर हैं कृषि पर निर्भरता और सीमित औद्योगिक अवसर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। "परिणामस्वरूप परिवार की आय में असमानता पैदा हो गई है और अधिकांश ग्रामीण परिवार गरीबी रेखा के आसपास जीवनयापन कर रहे हैं।"[12]

शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी संतोषजनक नहीं है। प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ी है, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा की स्थिति कमजोर है। विद्यालयों में अधोसंरचना की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति और बाल श्रम जैसी समस्याएँ शिक्षा के अवसर को सीमित करती है। "महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है, जो लैंगिक असमानता को और अधिक मजबूत करती है।"[13]

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति गंभीर चुनौतियों से भरी हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप–स्वास्थ्य केंद्र की संख्या पर्याप्त नहीं है और जो उपलब्ध है उनमें भी संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। यह स्थिति ICDS जैसी योजनाओं के महत्व को और बढ़ा देती है, क्योंकि यह योजना पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर को भरने में योगदान दे रही है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्रामीण भागलपुर में सामुदायिक नेटवर्क और पारिवारिक संबंध मजबूत है, लेकिन पितृसत्तात्मक संरचनाएँ अब भी प्रभावी है। "महिलाओं की निर्णय–प्रक्रिया में भागीदारी सीमित है, हालाँकि आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इसमें धीरे–धीरे परिवर्तन हो रहा है।"[14]अतः यह स्पष्ट है ग्रामीण भागलपुर का सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य गहरे असमानता संसाधनों की कमी और विकास की चुनौतियों से भरा हुआ है। इसी संदर्भ में ICDS योजना के प्रभाव को समझना अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह योजना बच्चों और महिलाओं जैसे सबसे कमजोर वर्गों को लक्षित करके ग्रामीण समाज में संतुलन और सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।

भागलपुर में ICDS का कार्यान्वयनः संस्थागत तंत्र के रूप में

ICDS योजना का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है, इसका कार्यान्वयन स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से हो रहा है। भागलपुर ज़िले के आंगनवाड़ी केंद्र इस योजना की आधारभूत इकाई है, जो बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण, स्वास्थ्य और प्री–स्कूल शिक्षा जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। "केंद्र न केवल सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करता है, ग्रामीण समुदाय और राज्य के बीच एक सेतु का कार्य भी करता है।"[15]

संस्थागत ढाँचे की दृष्टि से प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायिका नियुक्त की जाती है। कार्यकर्ता का दायित्व है, वह बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराए, स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद करे और प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों का संचालन करे। सहायिका इस प्रक्रिया में सहयोग देती है और स्थानीय स्तर पर सामुदायिक संबंध को सुदृढ़ करती है। इसके अतिरिक्त, "आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आशा कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय स्थापित कर काम करती है।"[16]भागलपुर ज़िले में ICDS योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) और पर्यवेक्षकों के माध्यम से संचालित होता है। CDPO योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण का दायित्व निभाते हैं, जबकि पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करते हैं। इसके बावजूद, "कई बार संसाधनों की कमी, स्टाफ की अनुपलब्धता और वित्तीय विलंब के कारण योजनागत उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावित होती है।"[17]

NFHS-5 (2019–21) के आधार पर भागलपुर जिले और बिहार राज्य से जुड़े प्रमुख पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों की सारणी और इसके विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो योजना के प्रभाव को दर्शाता हैः–

---

10 भारत की जनगणना. (2011). *जिला जनगणना पुस्तिका: भागलपुर*. नई दिल्ली: भारत सरकार।

11 झा, एस. (2019). *ग्रामीण बिहार में जाति, पोषण और बाल स्वास्थ्य: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट*, 19(2), 101–120।

12 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO). (2020). *बिहार में घरेलू उपभोग और सामाजिक संकेतक: NSS 76वां चक्र (2018–19)*. नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

13 जिला सांख्यिकीय पुस्तिका. (2022). *जिला सांख्यिकीय पुस्तिका: भागलपुर 2022*. पटना: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार।

14 कुमार, आर. (2020). *लैंगिकता, समुदाय और सामाजिक परिवर्तन: ग्रामीण बिहार का अध्ययन*. पटना: आनंदिका पब्लिशर्स।

15 बिहार सरकार. (2021). *एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) वार्षिक रिपोर्ट 2020–21*. पटना: सामाजिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार।

16 बसु, एम., एवं दास, एस. (2018). *ICDS के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी और महिला सशक्तिकरण: ग्रामीण भारत का अध्ययन*. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।

17 पटेल, डी. (2019). *भारत के पिछड़े जिलों में ICDS के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: क्षेत्राधारित अध्ययन. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़*, 35(3), 133–150।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

1. बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम (योजना का मुख्य प्रभाव)

योजना का एक मुख्य उद्देश्य 0–5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण को कम करना है। निम्नलिखित सारणी में भागलपुर बच्चों के पोषण स्तर को बिहार राज्य के औसत से किया गया है (NFHS-5 डेटा पर आधारित):

सारणी 1: बच्चों में कुपोषण की स्थिति (5 वर्ष से कम आयु)

संकेतक	भागलपुर जिला (NFHS-5, प्रतिशत)	बिहार राज्य (NFHS-5, प्रतिशत)	विश्लेषण
नाटापन (Stunting)	47 प्रतिशत	42.9 प्रतिशत	भागलपुर में नाटापन का स्तर राज्य के औसत से काफी अधिक है, जो दर्शाता है कि ICDS सहित अन्य पोषण कार्यक्रमों को बच्चों के दीर्घकालिक पोषण में सुधार हेतु और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।
दुबलापन (Wasting)	23 प्रतिशत	22.9 प्रतिशत	दुबलापन राज्य के औसत के लगभग बराबर है, जो अपर्याप्त आहार या दुबलापन को दर्शाता है।
कम वजन (Underweight)	41 प्रतिशत	41.0 प्रतिशत	कम वजन का स्तर राज्य के औसत के बराबर है। यह आंकड़ा ICDS के तहत दिए जाने वाले पूरक पोषाहार की निरंतर और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
एनीमिया (Anemia)	79 प्रतिशत	69.4 प्रतिशत	भागलपुर में एनीमिया (खून की कमी) का स्तर राज्य के औसत (69.4 प्रतिशत) से काफी अधिक है, जो बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता के लिए एक गंभीर चुनौती है।

Graph 1: Child Nutrition Outcomes (Children under 5 years) - NFHS-5

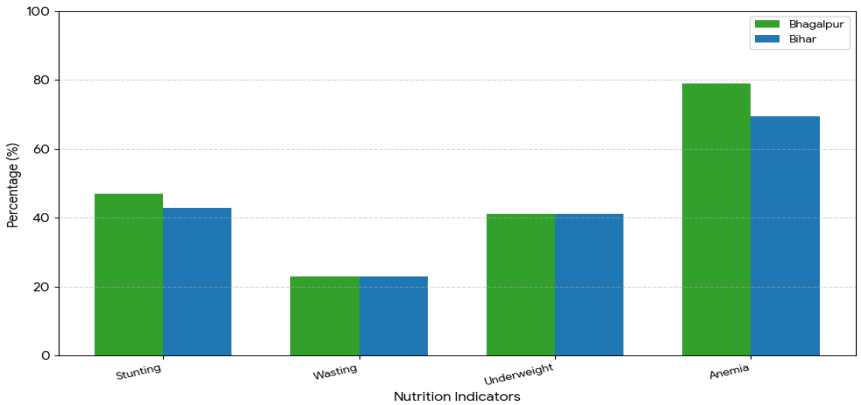

2. ICDS की प्रमुख सेवाएँ एवं इसका कार्यान्वयन

योजना की सेवाओं में पूरक आहार के साथ–साथ गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा प्रदान करना भी शामिल है। इस प्रकार के संकेतक ICDS के कार्यान्वयन के स्तर को दर्शाता है।

सारणी 2: ICDS से संबंधित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ

संकेतक	भागलपुर जिला (NFHS-5, प्रतिशत)	बिहार राज्य (NFHS-5, प्रतिशत)	विश्लेषण
संस्थागत प्रसव (Institutional Births)	69.4 प्रतिशत	76.8 प्रतिशत	संस्थागत प्रसव का स्तर राज्य के औसत से कम है, जिससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।
स्तनपान की शीघ्र शुरुआत	28.0 प्रतिशत	43.4 प्रतिशत	प्रसव के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने की दर भागलपुर में राज्य के औसत से बहुत कम है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

(Early Initiation of Breastfeeding)			यह ICDS के तहत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के कमजोर प्रभाव को इंगित करता है।
अनन्य स्तनपान (Exclusive Breastfeeding, 6 माह तक)	62.0 प्रतिशत	58.9 प्रतिशत	इस महत्वपूर्ण संकेतक पर भागलपुर का प्रदर्शन राज्य के औसत से बेहतर है।
गर्भावस्था के दौरान 100+ दिन IFA का सेवन	28.0 प्रतिशत	26.7 प्रतिशत	गर्भवती महिलाओं द्वारा एनीमिया-रोधी गोलियों (IFA) का पर्याप्त सेवन राज्य के औसत से थोड़ा अधिक है, जो ICDS/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रयास को दर्शाता है।

Graph 1: Child Nutrition Outcomes (Children under 5 years) - NFHS-5

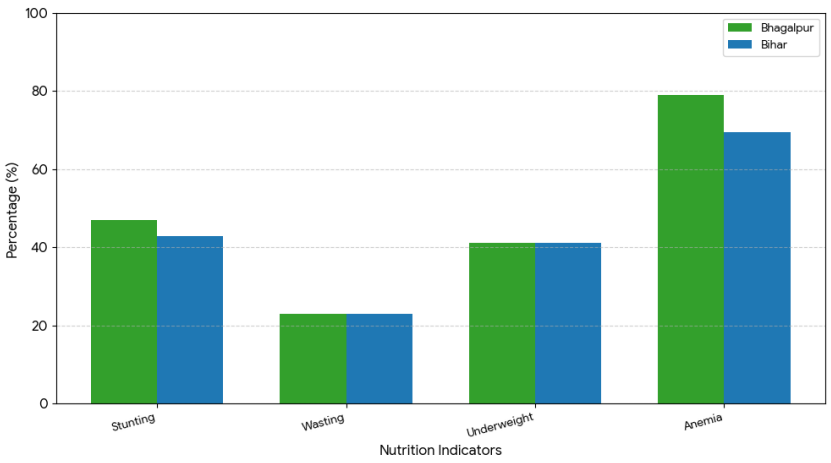

उपर्युक्त आँकड़ों के आधार पर भागलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ICDS योजना के प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण निम्नलिखित हैः

1. पहुँच में असमानता एवं गुणवत्ता की चुनौतीः– भागलपुर के बच्चों में पोषण के प्रमुख संकेतक नाटापन एवं खून की कमी (Stunting/Anemia) राज्य के औसत से खराब है। यह दर्शाता है, ICDS सेवा की पहुँच (Access) या गुणवत्ता (Quality) में कमी है, विशेषकर सबसे गरीब और सबसे पिछड़े ग्रामीण समुदायों में, जहाँ दीर्घकालिक कुपोषण (Stunting) और एनीमिया एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

2. व्यवहार परिवर्तन की धीमी गतिः– ICDS का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन लाना है, जैसे स्तनपान की शीघ्र शुरुआत। भागलपुर में इसकी दर बहुत कम होना सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं (Social and Cultural Practices) पर प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप न कर पाने को दर्शाता है। योजना कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करने में और अधिक सामाजिक–सांस्कृतिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है।

3. सकारात्मक संकेतः– छह माह तक के बच्चों में अनन्य स्तनपान की दर राज्य के औसत से बेहतर होना एक सकारात्मक संकेत है। योजना कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी सेविका) के प्रयासों से समुदाय–स्तर पर एक सफल व्यवहार परिवर्तन की संभावना को इंगित करता है, जिस पर आगे ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

योजना के कार्यान्वयन में सामुदायिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्राम स्तर पर माता–पिता और समुदाय के अन्य सदस्य आंगनवाड़ी गतिविधि जैसे– पोषण दिवस, स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। "इस सहभागिता से न केवल योजना की स्वीकार्यता बढ़ती है, यह स्थानीय सामाजिक पूंजी को भी मजबूत करता है।"[18]

भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में के संस्थागत तंत्र को कई चुनौतियों जैसे आंगनवाड़ी केंद्रो का अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, भवन और उपकरणों की कमी, समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति में रुकावट और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त "कुछ क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ और जातिगत पूर्वाग्रह योजना की पहुँच को सीमित करता है, जिससे कमजोर वर्गों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है।"[19]

[18] कबीर, एन. (2001). *महिला सशक्तिकरण के मापन पर चिंतन. डिस्कसिंग विमेन्स एम्पावरमेंट: थ्योरी एंड प्रैक्टिस* (पृ. 69–88). स्टॉकहोम: सिडा स्टडीज़।

[19] झा, एस. (2019). *ग्रामीण बिहार में जाति, पोषण और बाल स्वास्थ्य: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट*, 19(2), 101–120।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

इसके बावजूद ICDS ने भागलपुर के ग्रामीण इलाकों में कई सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पोषण आहार की नियमित उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता और महिलाओं की सामाजिक भूमिका में सुधार इसके प्रमुख परिणाम हैं। इस प्रकार, संस्थागत तंत्र की मजबूती और इसकी सामाजिक स्वीकृति, योजना की सफलता के अनिवार्य तत्व हैं। संक्षेप में, भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ICDS योजना ने कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव दिखाया है (जैसे अनन्य स्तनपान), लेकिन कुपोषण और एनीमिया उच्च स्तर दर्शाता है, योजना के गहन सामाजिक और आर्थिक प्रभाव (Deep Sociological and Economic Impact) को प्राप्त करने के लिए सेवा वितरण और गुणवत्ता को मजबूत करने की आवश्यकता है।

बाल पोषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव

योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शिशुओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। भागलपुर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना कुपोषण और बाल मृत्यु दर जैसी गंभीर समस्याओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को पूरक आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और विकास निगरानी जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है।"[20]

ग्रामीण भागलपुर में किए गए अध्ययन के अनुसार, ICDS योजना बाल पोषण की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। पहले जहाँ अधिकांश परिवार बच्चों को केवल पारंपरिक आहार तक सीमित रखते थे, वहीं अब पूरक पोषण आहार जैसे–दलिया, खिचड़ी और अंडे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के कारण, बच्चों के पोषण स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। इसके अलावे, "गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी आयरन की गोलियाँ, टीकाकरण और स्वास्थ्य परामर्श दिया जाता है, जिससे शिशुओं के स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है।"[21] टीकाकरण कवरेज में भी ICDS योजना की भूमिका उल्लेखनीय है। आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से 'स्वास्थ्य और पोषण दिवस' आयोजित करता है, जहाँ बच्चों को टीकाकरण के साथ–साथ माताओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्रदान की जाती है। "इससे बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है और कई संक्रामक रोगों के रोकथाम में सफलता प्राप्त हुई है।"[22]

योजना के प्रभाव में असमानताएँ पाई गई है। जिस गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र सक्रिय है। वहाँ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है वहाँ बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में स्पष्ट सुधार देखा गया है, जबकि जिन क्षेत्रों में केंद्र का ढाँचा कमजोर है या स्टाफ की अनुपस्थिति रहती है, वहाँ अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। "कई बार खाद्यान्न की आपूर्ति में देरी और गुणवत्ताहीन भोजन, योजना के उद्देश्यों को प्रभावित करता है।"[23]

सामाजिक दृष्टि से योजना माताओं और परिवारों में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया है। पहले जहाँ बच्चों के बीमारियों को अंधविश्वास या घरेलू उपचारों से जोड़ा जाता था, वहीं अब माताएँ टीकाकरण, चिकित्सकीय जाँच और संतुलित आहार को महत्व दे रही है। "इस प्रकार के परिवर्तन से न केवल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक दिशा प्रदान करता है, बल्कि ग्रामीण समाज में आधुनिक स्वास्थ्य चेतना के प्रसार का भी संकेत देता है।"[24]

इस प्रकार योजना भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस दिशा में अभी भी कई चुनौती है, जिसे दूर करना आवश्यक है ताकि सभी बच्चों को समान रूप से इस योजना का लाभ प्राप्त हो।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक भागीदारी पर प्रभाव

योजना केवल बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है; इसका प्रभाव ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति और सशक्तिकरण पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में नियुक्त महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने से उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है और उन्हें सामाजिक पहचान मिली है। "इससे ग्रामीण महिलाओं का पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना और समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाना संभव हुआ है।"[25]

भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के माध्यम से महिलाओं ने कई सामाजिक और आर्थिक गतिविधि में भागीदारी की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका न केवल बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करती है, वे माता–पिता को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता का संदेश भी देती है। "यह कार्य महिलाओं के लिए नेतृत्व, संचार और संगठनात्मक कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।"[26]

इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी केंद्र स्थानीय सामुदायिक नेटवर्क का भी केंद्र है। महिलाएँ इन केंद्रों पर नियमित रूप से मिलती है, आपसी अनुभव साझा करती है और सामूहिक समस्याओं पर चर्चा करती है। इससे "महिलाओं में सामूहिक कार्रवाई की भावना और सामाजिक पूंजी (Social Capital) का निर्माण होता है, जो ग्रामीण समाज में पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचना के भीतर महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देता है।"[27]

---

[20] **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण** (*NFHS-5). (2019–2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019–21: बिहार एवं भागलपुर जिला तथ्यपत्र.* मुंबई: अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

[21] कुमार, आर. (2020). *लैंगिकता, समुदाय और सामाजिक परिवर्तन: ग्रामीण बिहार का अध्ययन.* पटना: आनंदिका पब्लिशर्स।

[22] झा, एस. (2019). *ग्रामीण बिहार में जाति, पोषण और बाल स्वास्थ्य: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट*, 19(2), 101–120।

[23] पटेल, डी. (2019). *भारत के पिछड़े जिलों में ICDS के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: क्षेत्राधारित अध्ययन. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़*, 35(3), 133–150।

[24] सेन, ए., एवं द्रेज़, जे. (2013). *अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स.* प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

[25] कबीर, एन. (2001). *महिला सशक्तिकरण के मापन पर चिंतन. डिस्कसिंग विमेन्स एम्पावरमेंट: थ्योरी एंड प्रैक्टिस* (पृ. 69–88). स्टॉकहोम: सिडा स्टडीज़।

[26] बोस, अ. (2017). *भारत में महिला कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी प्रणाली. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 52(23), 85–89।

[27] पटनम, आर. (2000). *बोलिंग अलोन: अमेरिकन समुदाय का पतन और पुनरुत्थान.* न्यूयॉर्क: साइमन एंड शुस्टर।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया चुनौतियों से मुक्त नहीं है। कई ग्रामीण परिवारों में महिलाएँ घरेलू जिम्मेदारियों और पारंपरिक सामाजिक मानदंडों के कारण आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक गतिविधियों में सीमित रूप से ही भाग ले पाती है। इसके अलावे, "कार्यकर्ताओं का सीमित प्रशिक्षण और अपर्याप्त वेतन एवं उनकी कार्यक्षमता और सामाजिक मान्यता को प्रभावित करता है।"[28]

योजना महिलाओं के जीवन में एक नई पहचान और सामूहिक शक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। योजना केवल आर्थिक सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, यह महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, निर्णय–निर्माण क्षमता और सामुदायिक नेतृत्व की संभावनाओं में वृद्धि करता है। योजना भागलपुर के ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सहभागिता में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके प्रभाव से महिलाओं का आत्मविश्वास सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है, उनका सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हुआ है और वे अपने परिवार तथा समुदाय में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है।

चुनौतियाँ और कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधायें

भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का कार्यान्वयन कई सकारात्मक परिणामों के बावजूद, अनेक चुनौतियों और सीमाओं का सामना कर रहा है। इस प्रकार की सीमाएँ न केवल योजना की प्रभावशीलता को कम करता है, बल्कि कमजोर **वर्ग** तक इसके लाभ पहुँचाने की क्षमता को भी सीमित करता है।

सबसे प्रमुख चुनौती संसाधनों की अपर्याप्तता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रायः भवन और उपकरणों की कमी होती है। "कई केंद्रों में बच्चों के बैठने और भोजन कराने के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे सेवा वितरण प्रभावित होता है।"[29] इसके साथ ही, खाद्यान्न और पोषण आहार की आपूर्ति में अनियमितता भी एक गंभीर समस्या है। "कभी–कभी भोजन की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है, जिससे बच्चों के पोषण स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।"[30]

मानव संसाधन की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण भी एक बड़ी बाधा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित प्रशिक्षण नहीं मिलता है, जिससे बच्चों के विकास, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा संबंधी गतिविधि प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त, "कर्मियों का वेतन और मान्यता अपर्याप्त होने के कारण कार्यक्षमता और मनोबल प्रभावित होता है।"[31]

सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ भी कार्यान्वयन में रुकावट डालती है। ग्रामीण समाज में जाति–आधारित भेदभाव और लैंगिक असमानताएँ कई बार बच्चों और महिलाओं तक सेवाओं की पहुँच को सीमित करता है। "कुछ समुदाय में महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी और बच्चों के पोषण पर ध्यान देने की संस्कृति काफी सीमित है, जिससे योजना की प्रभावशीलता घटती है।"[32] भ्रष्टाचार और निगरानी की कमी भी कार्यान्वयन की चुनौतियों में शामिल है। आंगनवाड़ी केंद्रों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन में कमी होने के कारण संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है। योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी आवश्यकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, योजना भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाया है। योजना की पूर्ण सफलता के लिए संस्थागत सुधार, संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता, प्रशिक्षण और निगरानी के बेहतर तंत्र और सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयास आवश्यक है।

अतः यह कहा जा सकता है कि ICDS योजना का कार्यान्वयन बहुआयामी चुनौतियों से घिरा हुआ है और इसकी प्रभावशीलता स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भों पर निर्भर करती है। सुधार के उपाय केवल प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों तक सीमित नहीं होने चाहिए, स्थानीय सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक संदर्भों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

तुलनात्मक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

योजना के प्रभाव का विश्लेषण केवल भागलपुर तक सीमित नहीं है। अन्य राज्यों और क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन से यह समझने में मदद मिलती है,विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भ योजना की सफलता को किस प्रकार प्रभावित करता है।विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में योजना के कार्यान्वयन के अनुभव ने स्पष्ट किया है, "योजनागत सफलता में केवल संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं, समुदाय की सहभागिता, शासन की पारदर्शिता और महिलाओं के सशक्तिकरण की रणनीतियाँ भी निर्णायक भूमिका निभाता है।"[33]

केरल में, ICDS केंद्र का बेहतर भौतिक ढाँचा, प्रशिक्षित और नियमित वेतन पाने वाली कार्यकर्ता तथा पंचायत स्तर पर सक्रिय निगरानी ने योजना की प्रभावशीलता में वृद्धि किया है। आंगनवाड़ी केंद्र केवल पोषण और शिक्षा का केंद्र नहीं है, यह महिलाओं के सामूहिक नेतृत्व और सामाजिक पूंजी के विकास का भी माध्यम है। तुलनात्मक दृष्टि से, "भागलपुर में कई केंद्र अभी भी आधारभूत संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता से जूझ रहा है।"[34]

---

[28] पटेल, डी. (2019). *भारत के पिछड़े जिलों में ICDS के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: क्षेत्राधारित अध्ययन. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़*, 35(3), 133–150।

[29] बिहार सरकार. (2021). *एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) वार्षिक रिपोर्ट 2020–21*. पटना: सामाजिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार।

[30] झा, एस. (2019). *ग्रामीण बिहार में जाति, पोषण और बाल स्वास्थ्य: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट*, 19(2), 101–120।

[31] पटेल, डी. (2019). *भारत के पिछड़े जिलों में ICDS के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: क्षेत्राधारित अध्ययन. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़*, 35(3), 133–150।

[32] सेन, ए., एवं द्रेज़, जे. (2013). *अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स*. प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

[33] देविका, जे., एवं थम्पी, बी. वी. (2011). *केरल में नये लोकतांत्रिक स्थान: कूडुम्बश्री पहल. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 46(9), 77–85।

[34] बोस, अ. (2017). *भारत में महिला कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी प्रणाली. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 52(23), 85–89।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

तमिलनाडु में योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और महिला समितियों की सक्रिय भागीदारी योजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुदाय का प्रत्यक्ष जुड़ाव न केवल योजना के लाभ को सुनिश्चित करता है, सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव को भी कम करने में मदद करता है। "भागलपुर में इस दृष्टिकोण का आंशिक पालन देखने को मिला है, लेकिन सामाजिक संस्तरण और पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचना के कारण महिलाओं की सहभागिता अभी भी सीमित है।"[35]

मध्य प्रदेश में ICDS के क्रियान्वयन में निगरानी और मूल्यांकन की प्रणाली को डिजिटल माध्यम और सामाजिक ऑडिट के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका सिद्ध हुआ है। "भागलपुर में निगरानी तंत्र अभी भी पारंपरिक और आंशिक है, जिससे संसाधनों का उचित उपयोग और योजना की जवाबदेही प्रभावित होती है।"[36]

तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है, योजना की सफलता केवल सरकारी नीति और बजट पर निर्भर इसके लिए स्थानीय सामाजिक संरचना, समुदाय की भागीदारी, महिलाओं का सशक्तिकरण और प्रभावी निगरानी तंत्र भी अनिवार्य है। भागलपुर में योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अन्य राज्यों की नीतियों और प्रथाओं से सीख लेना आवश्यक है।

अतः समाजशास्त्रीय दृष्टि से, योजना का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है, योजना के सकारात्मक परिणाम केवल संसाधनों और प्रशासनिक प्रयासों पर ही नहीं, सामाजिक सहभागिता, सामुदायिक समर्थन और लैंगिक सशक्तिकरण की व्यापक प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है।

निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझाव

अध्ययन के निष्कर्ष से स्पष्ट है, योजना भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाने में सफलतम योजनाओं में एक है। बाल पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, प्रारंभिक शिक्षा और माताओं के सशक्तिकरण में योजना का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आंगनवाड़ी केंद्र केवल सेवाओं के वितरण का माध्यम नहीं है, यह "ग्रामीण समाज में सामाजिक पूंजी, सहभागिता और सामूहिकता के निर्माण का भी आधार तैयार करता है।"[37]

सामाजिक दृष्टि से योजना ने महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका न केवल रोजगार और सामाजिक पहचान पाती है, वे सामुदायिक नेतृत्व और सामाजिक नेटवर्क का हिस्सा बन रही है। "इससे ग्रामीण महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।"[38]

वर्तमान अध्ययन के आधार पर, योजना को अभी भी कई चुनौतियों और सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है। संसाधनों की अपर्याप्तता, प्रशिक्षण और वेतन की कमी, सामाजिक असमानताएँ, निगरानी की अपर्याप्तता और प्रशासनिक बाधाएँ योजना की प्रभावशीलता पर नकारात्मक असर डालती है। इस कारण से "सभी लाभार्थियों तक योजना का समुचित लाभ प्राप्त होना अभी भी एक चुनौती है।"[39]

नीति सुझाव :

1. **संसाधनों की उपलब्धता बढ़ानाः** आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन, उपकरण और पोषण आहार की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए।
2. **मानव संसाधन का सुदृढ़ीकरणः** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित प्रशिक्षण, उचित वेतन और सामाजिक मान्यता प्रदान किया जाना चाहिए।
3. **सामुदायिक सहभागिताः** स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और महिला समितियों को आंगनवाड़ी केंद्रों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
4. **निगरानी और पारदर्शिताः** डिजिटल माध्यमों और सामाजिक ऑडिट के द्वारा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
5. **सामाजिक असमानताओं को दूर करनाः** जाति–आधारित भेदभाव और लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और संवेदनशीलता प्रशिक्षण आवश्यक है।
6. **नवीन दृष्टिकोण और अनुसंधानः** योजना की प्रभावशीलता का नियमित समाजशास्त्रीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे नीतिगत सुधार और स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना में सुधार संभव हो।

अंततः, ICDS योजना ग्रामीण समाज में केवल पोषण और स्वास्थ्य सुधार का माध्यम नहीं है, यह महिलाओं के सशक्तिकरण, सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण घटक है। यदि नीतिगत सुधार और संस्थागत मजबूती सुनिश्चित की जाए, तो ICDS योजना भागलपुर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सतत सामाजिक विकास और समान अवसर सुनिश्चित करने में और अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ–सूची

1. कबीर, एन. (2001). महिला सशक्तिकरण के मापन पर चिंतन. डिस्कसिंग विमेन्स एम्पावरमेंटः थ्योरी एंड प्रैक्टिस

[35] कबीर, एन. (2001). *महिला सशक्तिकरण के मापन पर चिंतन. डिस्कसिंग विमेन्स एम्पावरमेंटः थ्योरी एंड प्रैक्टिस* (पृ. 69–88). स्टॉकहोम: सिडा स्टडीज़।

[36] पटेल, डी. (2019). *भारत के पिछड़े जिलों में ICDS के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: क्षेत्राधारित अध्ययन. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़*, 35(3), 133–150।

[37] सेन, ए., एवं द्रेज़, जे. (2013). *अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स*. प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

[38] कबीर, एन. (2001). *महिला सशक्तिकरण के मापन पर चिंतन. डिस्कसिंग विमेन्स एम्पावरमेंटः थ्योरी एंड प्रैक्टिस* (पृ. 69–88). स्टॉकहोम: सिडा स्टडीज़।

[39] पटेल, डी. (2019). *भारत के पिछड़े जिलों में ICDS के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: क्षेत्राधारित अध्ययन. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़*, 35(3), 133–150।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

(पृ. 69–88). स्टॉकहोमः सिडा स्टडीज़।
2. कुमार, आर. (2020). लैंगिकता, समुदाय और सामाजिक परिवर्तनः ग्रामीण बिहार का अध्ययन. पटनाः आनंदिका पब्लिशर्स।
3. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका. (2022). जिला सांख्यिकीय पुस्तिकाः भागलपुर 2022. पटनाः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार।
4. झा, एस. (2019). ग्रामीण बिहार में जाति, पोषण और बाल स्वास्थ्यः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, 19(2), 101–120।
5. देविका, जे., एवं थम्पी, बी. वी. (2011). केरल में नये लोकतांत्रिक स्थानः कूडुम्बश्री पहल. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 46(9), 77–85।
6. पटनम, आर. (2000). बोलिंग अलोनः अमेरिकन समुदाय का पतन और पुनरुत्थान. न्यूयॉर्कः साइमन एंड शुस्टर।
7. पटेल, डी. (2019). भारत के पिछड़े जिलों में ICDS के क्रियान्वयन की चुनौतियाँः क्षेत्राधारित अध्ययन. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़, 35(3), 133–150।
8. पार्सन्स, टी. (1951). द सोशल सिस्टम. ग्लेंको, इलिनॉयः फ्री प्रेस।
9. बसु, एम., एवं दास, एस. (2018). ICDS के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी और महिला सशक्तिकरणः ग्रामीण भारत का अध्ययन. नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स।
10. बिहार सरकार. (2021). एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) वार्षिक रिपोर्ट 2020–21. पटनाः सामाजिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार।
11. बोस, अ. (2017). भारत में महिला कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी प्रणाली. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 52(23), 85–89।
12. भारत की जनगणना. (2011). जिला जनगणना पुस्तिकाः भागलपुर. नई दिल्लीः भारत सरकार।
13. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO). (2020). बिहार में घरेलू उपभोग और सामाजिक संकेतकः NSS 76वां चक्र (2018–19). नई दिल्लीः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
14. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5). (2019–2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5), 2019–21: बिहार एवं भागलपुर जिला तथ्यपत्र. मुंबईः अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
15. सेन, ए., एवं द्रेज़, जे. (2013). अनसर्टेन ग्लोरीः इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स. प्रिंसटनः प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।